नईदुनिया

यूएई ने ईरान को दिया समुद्री नौवहन पर हमले का जवाब सभी तरह के व्यापारिक रिश्ते तोड़े, अमेरिकी तेवर भी कठोर

अबूधाबी/वाशिंगटन

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बड़ा कदम उठाया है। यूएई ने तत्काल प्रभाव से ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी। यूएई ने यह कदम क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए उठाया है।

यूएई विदेश मंत्रालय के रणनीतिक संचार विभाग की निदेशक अफरा अल हमेली ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेंगे। मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। होर्मुज जलडमरूमध्य अब अमेरिकी क्षेत्र में है।

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री नौवहन (जलपरिवहन मार्गदर्शन) निशाना बनाने वाली ईरान की दो बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में गिरने के बाद, यूएई ने ईरान के साथ सभी गतिविधियों, व्यापारिक लेन-देन और वित्तीय लेन-देन को अगले आदेश तक रोक दिया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमित समुद्री यातायात और एक जहाज पर हमले की सूचना के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य खुला और चालू है। ट्रंप ने इस जलमार्ग को नया अमेरिकी क्षेत्र बताने वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की हैष ईरान ने जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए अपनी शर्तें दोहराई हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापक यूएस-ईरान बातचीत फिर से शुरू होने से पहले मध्यस्थ होर्मुज पर ईरान-ओमान के बीच द्विपक्षीय समझौते का इंतजार कर रहे हैं।

यूएई विदेश मंत्रालय के रणनीतिक संचार विभाग की निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि आर्थिक संबंधों पर ईरान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अल हामेली ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता को दोहराया। अल हामेली ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कमर्शियल लेन-देन और वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी गई है। ये उपाय अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने देशवासियों से कहा कि वह सिर्फ सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करें।

न्यूज ब्रीफ

नाजी सेना की मोटरसाइकिल और बारूद का जखीरा बरामद

बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूरोप की प्रसिद्ध डेन्यूब नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े एक बड़े रहस्य का पर्दाफाश हुआ है। हिटलर की नाजी सेना से संबंधित एक पूरी मोटरसाइकिल और बारूद का खतरनाक जखीरा नदी के तल से बरामद किया गया है। दशकों तक कीचड़ में दबी यह वेहरमाख्ट की डीकेडब्ल्यू एनजेड 350-1 माडल की मोटरसाइकिल लगभग पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में मिली है। यह असाधारण खोज बुडापेस्ट के संसद भवन के पास डेन्यूब नदी के तल में हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय मिलिट्री हिस्ट्री इंस्टीट्यूट ने इस खोज को सौ साल में एक बार होने वाली घटना बताया है। नदी की मिट्टी ने इसे प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखा है। यह विशेष युद्धकालीन मोटरसाइकिल 1944 से निर्मित की जा रही थी और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक इसकी लगभग 12,000 यूनिट्स तैयार की गई थीं। इससे पहले वाले माडल डीकेडब्ल्यू एनजेड 350 की शीर्ष गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जाती है। इस मोटरसाइकिल का निर्माण आटो यूनियन एजी ने किया था, जो 1932 में आडी सहित कई कंपनियों के विलय से बनी थी। एनजेड सीरीज के 250 और 350 माडल 1936 तक तैयार हो गए थे, लेकिन दूसरे माडल की अधिक बिक्री के चलते इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन 1938 में शुरू हुआ। तकनीकी तौर पर भी यह बाइक अपने समय से अलग थी। पहले के माडलों में फ्रेम के हिस्से बोल्ट से जुड़े होते थे, लेकिन एनजेड सीरीज में इन्हें वेल्ड किया गया था।

तीस्ता जल विवादः बांग्लादेश भारत के साथ नहीं बिगाड़ना चाहता संबंध, आपसी हितों के संतुलन पर दिया जोर

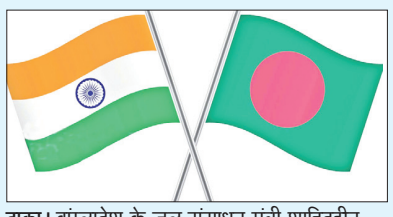

ढाका। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने साफ किया है कि उनका देश लंबे समय से अटके तीस्ता जल बंटवारा समझौते को लेकर भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण और द्विपक्षीय संबंधों को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता। हालांकि, उन्होंने नई दिल्ली से आग्रह किया है कि वह अपने हितों के साथ-साथ ढाका के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखे। एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहमान सरकार में मंत्री चौधरी ने कहा कि एक मित्र देश को दूसरे मित्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए और दोनों देशों को आपसी सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। यह बयान तब सामने आया है जब बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के जल प्रबंधन और समाधान के लिए नए सिरे से प्रयास तेज किए हैं। इसमें चीन के सहयोग से प्रस्तावित तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना शामिल है।

सदी के अंत तक चार घंटे अतिरिक्त करना पड़ सकता है गर्मी का सामनाः शोध

बीजिंग। यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और प्रदूषण मौजूदा गति से बढ़ता रहा, तो इस सदी के अंत तक हर गर्म दिन में औसतन चार घंटे अतिरिक्त भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी दी है शोध कर्ता वैज्ञानिकों ने। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बदलाव का सबसे अधिक असर निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ेगा, जहां पहले से ही गर्मी, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती हैं। शोध चीन की सन यात-सेन यूनिवर्सिटी और सदर्न मरीन साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्वांगडोंग लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने किया है। उनके अनुसार, अब तक गर्मी का आकलन मुख्य रूप से किसी दिन के अधिकतम या न्यूनतम तापमान के आधार पर किया जाता रहा है, लेकिन इससे दिन के उन घंटों का सही आकलन नहीं हो पाता, जब तापमान अचानक अत्यधिक स्तर तक पहुंच जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। वैज्ञानिकों ने वर्ष 1981 से 2023 तक के मौसम संबंधी आंकड़ों और भविष्य के जलवायु माडलों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान हर वर्ष औसतन 269 घंटे अत्यधिक गर्मी की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, वर्ष 1981 से 2023 के बीच पृथ्वी के 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग पर प्रत्येक दशक में औसतन 62 घंटे की अतिरिक्त भीषण गर्मी दर्ज की गई है, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाती है।

होर्मुज पर ट्रंप ने नक्शा पोस्ट कर कहा- यह अमेरिका का नया इलाका

वाशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले होर्मुज जलमार्ग के नियंत्रण को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक नक्शा साझा करते हुए इस प्रमुख समुद्री मार्ग को अमेरिका का नया इलाका करार दिया है। इस दावे के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल तेज हो गई है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे समुद्री मार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है, जो अब और अधिक गंभीर रूप लेती नजर आ रही है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे अहम मार्गों में शुमार इस जलमार्ग पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होने का दावा किया। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने दोहराया कि इस समुद्री मार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करना एक बेहतरीन विचार है और नाकाबंदी के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इससे पहले एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए भी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे। अमेरिका के इन बयानों के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरी हो गई हैं।

दूसरी तरफ, ईरान ने भी इस मामले पर अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक अमेरिका पूर्व में हुए समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता, तब तक यह समुद्री मार्ग बंद ही रहेगा। तेहरान की ओर से यह मांग की गई है कि वाशिंगटन अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को समाप्त करे, ईरान के तेल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए और विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्तियों को बहाल करे। ईरान का तर्क है कि ये सभी मुद्दे आपसी समझ का हिस्सा थे, जिनके लागू न होने के कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि जलमार्ग के ट्रांजिट और नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच कड़ा टकराव बना हुआ है।

इस बढ़ते तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। हाल ही में इस मार्ग से गुजर रहे एक वाणिज्यिक जहाज को किसी अज्ञात प्रक्षेप्य (प्रोजेक्टाइल) द्वारा टक्कर मारे जाने की खबर सामने आई है।

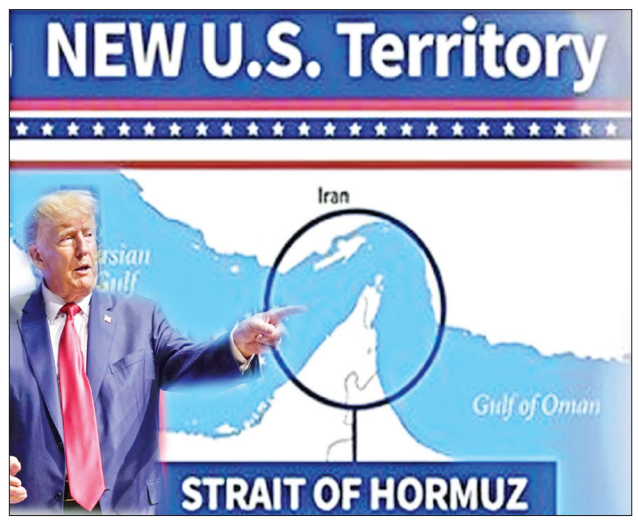

द्वितीय विश्व युद्ध के बिना फटे बमों और गोलों को सक्रिय कर रही आग

लंदन। यूरोप के जंगलों में भड़क रही भीषण आग जमीन में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के बिना फटे बमों और गोलों को सक्रिय कर रही है, जिससे वे अचानक फट रहे हैं। यह भीषण आग एक नए और जानलेवा खतरे को जन्म दे रही है। यह स्थिति न केवल आम लोगों के लिए घातक है, बल्कि दमकलकर्मियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जर्मनी के म्यूरिट्ज नेशनल पार्क में जुलाई में लगी आग के दौरान, दमकलकर्मियों को बम निरोधक दस्तों के साथ काम करना पड़ा क्योंकि जमीन के नीचे भारी मात्रा में युद्ध का गोला-बारूद दबा हुआ था। विस्फोट के डर से बचाव दल जंगल के कई हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाए। इसी तरह, फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी गिरोंड इलाके में 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र को राख करने वाली आग ने जमीन के अंदर से कम से कम 75 जिंदा गोले बाहर निकाल दिए। इनमें से कई गोले तेज आवाज के साथ फट गए। ले पोर्ज गांव के मेयर मार्शल जानीनेत्ती ने बताया कि उनके पास इन बमों की मौजूदगी का कोई रिकार्ड नहीं था। ब्रिटेन के नार्थ यार्कशायर के लैंगडेल मूर में भी 2025 में छह सप्ताह तक चली आग के दौरान 20 से अधिक गोले फटे थे, क्योंकि यह क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टैंक प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होता था। दशकों से शांत पड़े ये बम अब जमीन के अंदर आग की भीषण गर्मी और दबाव के कारण फट रहे हैं। पुरानी युद्ध सामग्री समय के साथ अस्थिर हो जाती है और उच्च तापमान पर उसके फ्यूज बेहद संवेदनशील होकर धमाके का कारण बन जाते हैं। जब आग कई घंटों या दिनों तक सुलगती रहती है, तो वह जमीन की गहराइयों तक भयानक गर्मी पहुंचाती है, जिससे दबे हुए गोला-बारूद में विस्फोट हो जाता है। यह संकट जलवायु परिवर्तन से सीधे जुड़ा है, जिसने यूरोप में जंगल की आग को पहले से कहीं अधिक विनाशकारी बना दिया है। स्पेन और फ्रांस में 2026 में लगी भीषण आग इसका स्पष्ट उदाहरण है। लगातार बढ़ती गर्मी और बारिश की कमी से मिट्टी की नमी खत्म हो रही है, जिससे आग को फैलने का मौका मिलता है। उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम में तो किसान आज भी जुताई के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के गोले निकालते हैं, जिन्हें लौह फसल या आयरन हार्वेस्ट कहा जाता है। प्रशासन और बचाव टीमों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें आग बुझाने के साथ-साथ इन अप्रत्याशित विस्फोटों से भी निपटना पड़ रहा है।

बांग्लादेश में जेल में कैद अवामी लीग की नेता दीपू मोनी के पति का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी दी

ढाका

बांग्लादेश अवामी लीग की नेता और पूर्वमंत्री डा. दीपू मोनी के पति तौफीक नवाज का ढाका के एक अस्पताल में निधन हो गया। दीपू मोनी के बड़े भाई जेआर वदूद टीपू ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नमाज-ए-जनाजा और दफनाने की जगह और समय के बारे में फैसला किया जाएगा। दीपू मोनी इस समय जेल में बंद हैं। उन्होंने पैरोल के लिए अर्जी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, जेल में बंद अवामी लीग की नेत्री दीपू मोनी के बड़े भाई जेआर वदूद टीपू ने बताया कि उनके बहनोई तौफीक नवाज का रात 10:27 बजे कान्टिनेंटल हास्पिटल (यूनाइटेड हास्पिटल) में निधन हुआ है। उनका अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। नवाज की नमाज-ए-जनाजा और दफनाने की जगह और समय के बारे में फैसला किया जाएगा। नवाज को 2019 में स्ट्रोक आया था।

बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय के पूर्व वकील और शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ नवाज को इसी वर्ष 27 मई को रिश्तेदार व्हीलचेयर पर अदालत ले गए थे ताकि वह तारीख पर आईं अपनी पत्नी से मिल सकें। पूर्व मंत्री डा. दीपू मोनी को 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद 19 अगस्त 2024 को ढाका के बारीधारा इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

वह इस समय मुंशीगंज जिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। बीच में तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें इलाज के लिए ढाका मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया था। वहां से ठीक होने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया था।उनके खिलाफ हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा भड़काने जैसे करीब 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से अदालत ने उन्हें आधिकारिक तौर पर 38 मामलों में गिरफ्तार दिखाया है।

जून 2026 में उन्हें उच्च न्यायालय से कुछ मामलों में अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अपीलीय डिवीजन ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। इस वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सकीं। पति तौफीक नवाज के निधन के बाद उनके वकीलों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंशीगंज जिला प्रशासन से पैरोल पर रिहाई की अर्जी लगाई है।

यूएस-दक्षिण कोरिया साझेदारी में मोड़, ईरान पर ना से ट्रंप खफा

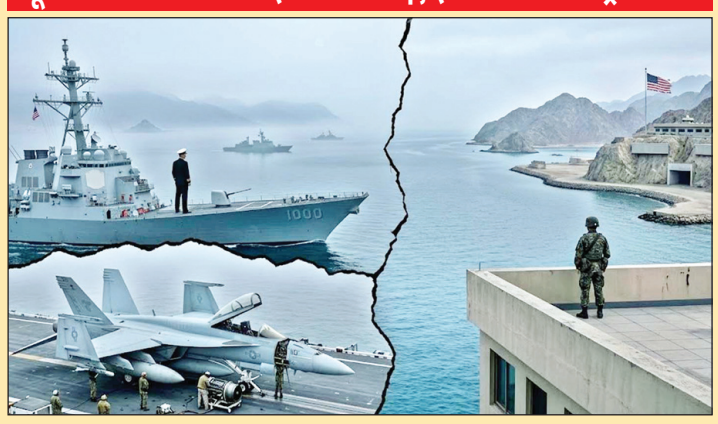

वाशिंगटन। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दशकों पुरानी सैन्य साझेदारी अचानक एक नाटकीय मोड़ पर आ खड़ी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल आफिस में पत्रकारों के सामने जो बातें कही, वे एक गहरे असंतोष और सवाल का इजहार थीं। ट्रंप ने साफ-साफ कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में मदद करने से इनकार कर दिया। यही इनकार अब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का बड़ा कारण बन गया है। ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को फोन किया और सीधा पूछा, क्या आप ईरान के मामले में हमारी मदद करेंगे अगर चाहें तो करें, हमें जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब आया, नो थैंक्स। बस यही वो पल था, जब अमेरिका की दक्षिण कोरिया को लेकर नीति बदल गई। ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है और ये जवाब उन्हें बुरी तरह चुभा। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, ठहरिये, हमारे 39 हजार सैनिक वहां तुम्हारे पड़ोसी किम जोंग उन से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी और तुम ईरान जैसे आसान सैन्य अभियान में हमारी मदद नहीं करोगे यह तो अजीब है। ट्रंप ने बार-बार दोहराया कि अमेरिका को ईरान में मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन सहयोगी देश अगर मदद से मुंह मोड़ ले तो फिर अमेरिका क्यों अरबों डालर खर्च करके उनकी सुरक्षा करे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नाटो से धोखा खाए हुए थे ।

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की जिजान रिफाइनरी को ड्रोन से बनाया निशाना

सना/रियाद

यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी लाल सागर तट पर स्थित जिजान में सऊदी अरामको की तेल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती मीडिया के अनुसार, यह हमला यमन के सादा और हज्जाह प्रांतों में कथित हवाई क्षेत्र उल्लंघन के जवाब में किया गया।

हूती समाचार एजेंसी सबा ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया कि समूह ने कई ड्रोन के जरिए जिजान स्थित अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया। हालांकि, हमले से हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है।

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ अपने हमले तेज करने के साथ ही समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की है। सऊदी अरब लंबे समय से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता रहा है और अतीत में हूती ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान चला चुका है।

हूतियों ने हाल के दिनों में सऊदी तेल टैंकरों और यमनी सरकारी बलों को भी निशाना बनाया है। समूह इससे पहले सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों पर कई हमले कर चुका है।

संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने इन हमलों की खबरों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से यमन व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में और अधिक उलझ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में पहले से जारी तनाव के बीच ऐसे हमलों से क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि हूती विद्रोहियों ने पिछले महीने ईरान के एक विमान के यमन की राजधानी सना में उतरने का भी स्वागत किया था। इसके बाद क्षेत्र में एक-दूसरे के खिलाफ हमलों का सिलसिला तेज हुआ है।

संवैधानिक पीठ के विरोध में चीफ जस्टिस को पत्र, बार एसोशिएशन ने दी बेंच बहिष्कार की चेतावनी

काठमांडू

नेपाल के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) डा. मनोज कुमार शर्मा द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर कनिष्ठ न्यायाधीशों को संवैधानिक पीठ में शामिल किए जाने के फैसले के विरोध में नेपाल बार एसोसिएशन ने बेंच बहिष्कार की चेतावनी दी है।

संवैधानिक पीठ के गठन में चली आ रही परंपरा के तहत वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल कर एकरूपता कायम करने की मांग करते हुए बार एसओशिएशन ने चीफ जस्टिस मनोज शर्मा का ध्यान आकर्षित कराया है। नेपाल बार एसोसिएशन ने प्रधानन्यायाधीश शर्मा को ध्यानाकर्षण पत्र भेजकर संवैधानिक इजलास के लिए दो में से किसी एक प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया है।

बार ने वरिष्ठता के आधार पर संवैधानिक पीठ के चार न्यायाधीशों का चयन करने का सुझाव दिया है। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो संवैधानिक पीठ के लिए निर्धारित न्यायाधीशों की सूची (रोस्टर) में शामिल न्यायाधीशों का चयन गोला प्रक्रिया के जरिए करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने संपत्ति जांच बूझ आयोग से संबंधित करीब छह रिट याचिकाओं को संवैधानिक पीठ में भेजने का आदेश दिया है। इन याचिकाओं को संवैधानिक इजलास में पेश किए जाने के बाद चीफ जस्टिस ने चार कनिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल कर संवैधानिक पीठ गठन करते हुए सुनवाई करने का निर्णय के बाद बार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

बार के अध्यक्ष विजय मिश्र ने संकेत दिया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अपना निर्णय नहीं बदला तो वे इन मामलों में बहस-पैरवी के लिए जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। हालांकि, इन मामलों की पेशी की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

नेपाल के संविधान की धारा 137 में प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में संवैधानिक इजलास के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत न्याय परिषद की सिफारिश पर प्रधानन्यायाधीश चार अन्य न्यायाधीशों का चयन करते हैं।

बार का कहना है कि उसने इससे पहले मौखिक रूप से अपनी मांगें रखी थीं, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बार ने संवैधानिक इजलास के गठन को लेकर कई बार आपत्ति जताई है।

बार ने अपने ध्यानाकर्षण पत्र में कहा है कि अन्य इजलास में विचाराधीन मामलों को भी प्रशासनिक निर्णय के आधार पर संबंधित पक्षों की सहमति और संबंधित पीठ में चर्चा किए बिना संवैधानिक पीठ में भेजे जाने की खबरों से वह और अधिक गंभीर तथा दुखी है। बार का कहना है कि मामलों की प्रकृति के आधार पर न्यायाधीशों का चयन किए जाने से पीठ की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे पीठ से किसी भी प्रकार का फैसला या आदेश आने पर विभिन्न प्रकार की आशंकाएं और प्रश्न पैदा होते हैं।